

Title: Reported death of infants due to malnutrition in tribal areas of Maharashtra.

MR. SPEAKER: I would not allow anybody. Nothing will be recorded. Now, I give the floor to Shri Anant Gangaram Geete.

(Interruptions) अॆँ*

* Not Recorded

श्री रामदास बंडु आठवले (पंढरपुर) : हमें भी बोलने का मौका दिया जाए।

MR. SPEAKER: Shri Ramdas Athawale, there is no notice from you. You just cannot stand up like this. I would not permit you to speak.

...(Interruptions)

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : अध्यक्ष जी, पिछले एक साल में महाराष्ट्र के 15 जिलों ठाणे, नासिक और विशोकर विदर्भ के कई जिलों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लगभग नौ हजार बालकों की मृत्यु हो गई। इन बालकों की उम्र छः साल से कम थी। इनकी मौत का मुख्य कारण कुपोषण था। उनको सही पोषण और पोषण के लिए आवश्यक आहार मिलना चाहिए था, जिसके न मिलने की वजह से इन नौ हजार बालकों की मृत्यु हो गई। यह जो रिपोर्ट है, सर्वे है, यह महाराष्ट्र सरकार का है। जब इस सर्वे को टाइम्स ऑफ इंडिया तथा दूसरे अखबारों ने पब्लिश किया तब महाराष्ट्र उच्च-न्यायालय के एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश श्री शाह ने एक जनहित याचिका दायर करवाई। इसी के साथ-साथ पीएमओ ने भी इस खबर को देखते हुए महाराष्ट्र के चीफ-सैक्रेट्री को बुलाकर इसकी रिपोर्ट मंगवाई है। आज महाराष्ट्र सरकार हर क्षेत्र में असफल हुई है और उस असफलता के कारण ट्राइबल-एरियाज के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो सहायता मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पा रही है। महाराष्ट्र की कुल आबादी का नौ प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जनजाति का है। अगर इस जनजाति को सही जी वनयापन करना है तो राज्य सरकार के बजट में कम से कम नौ सौ करोड़ रुपये का प्रावधान होना चाहिए जोकि उनकी मांग भी है। लेकिन राज्य सरकार ने केवल दो सौ करोड़ रुपये का प्रावधान ही पिछले साल किया है। धन की कमी के कारण राज्य सरकार इन अनुसूचित जनजाति के बालकों के पोषण के लिए सही योगदान नहीं दे पाई है। भारत सरकार के अनुसूचित जनजाति मंत्रालय की ओर से जो कई योजनाएं चलाई जाती हैं और धन का प्रावधान किया जाता है, मैं मांग करता हूं कि भारत सरकार महाराष्ट्र सरकार को अधिक धन की सहायता करे।

MR. SPEAKER: They have noted it.

श्री अनंत गंगाराम गीते : इसी के साथ-साथ पीएमओ ने जो इस ओर ध्यान दिया है और आज संसद का सत्र भी चल रहा है, इसलिए इस स्थिति के बारे में जो राज्य सरकार की वास्तविक स्थिति है, उसका निवेदन भारत सरकार की ओर से किया जाए। मैं राज्य सरकार की असफलता की निंदा करता हूं।

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : Sir, this is a very serious matter. The Government should respond to it. How can it be left like that? ...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Everybody is dictating to the Chair. There is a limit to this.

...(Interruptions)

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : Sir, this is a very serious matter.

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : अध्यक्ष जी, वैसे तो हमेशा महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों (व्यवधान)